NYCS

RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com

मई 2025, नई दिल्ली

अन्न भंडारण योजना

ग्रामीण युवाओं के रोजगार का नया अवसर

सहकारी डेयरी का विस्तार, बढ़ेगा ग्रामीण रोजगार ◀ अंदर के पन्नों पर ▶ युवाओं और सहकारिता का भविष्य संवारेगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP
IFFCO KISAN DRONE
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
IFFCO
NANO UREA PLUS
IFFCO
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop
इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"

युवा सहकार

वर्ष : 01, अंक-11, मई-2025

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं जीएम ऑफसेट, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92 द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

अन्न भंडारण से ग्रामीण सशक्तीकरण 04

ऑपरेशन सिंदूर: आतंक पर कड़ा प्रहार 05

06 ग्रामीण युवाओं के रोजगार का नया अवसर

18 अंत्योदय से विकसित भारत

सहकारी डेयरी का विस्तार, बढ़ेगा ग्रामीण रोजगार 14

आईटीआई का होगा कायाकल्प 20

दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखा रहे भारतीय युवा: पीएम 22

स्विगी पर मिलेंगे सहकारी उत्पाद 24

युवाओं में जागरूकता बढ़ाए एनवाईसीएस: नड्डा 25

टेस्ट को कोहली की अलविदा 28

पैक्स का कारोबारी दायरा बढ़ने से बदल रहा ग्रामीणों का जीवन 30

अन्न भंडारण से ग्रामीण सशक्तीकरण

योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, परिवहन लागत कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना है। गांवों में भंडारण और कृषि संबंधी अन्य सुविधाएं विकसित होने से सहकारी क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी जिससे विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसके प्रथम चरण के तहत देशभर के 500 पैक्स में गोदामों के निर्माण की शुरूआत हो चुकी है। अनाज भंडारण की कमी को दूर करने और विकेंद्रीकृत खाद्यान्न भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने मई 2023 में एक लाख करोड़ रुपये की इस योजना को मंजूरी दी थी जिसके तहत 7 करोड़ टन भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों में 9,750 टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है। इस योजना को सहकारी क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाना है।

इसमें पैक्स के स्तर पर विभिन्न कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जैसे विकेंद्रीकृत गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, छंटाई एवं ग्रेडिंग सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज, पैकहाउस आदि की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह योजना न केवल स्थानीय भंडारण को सक्षम बनाकर परिवहन एवं वितरण चुनौतियों का समाधान करेगी, बल्कि पैक्स को कृषि विपणन एवं खरीद प्रणालियों के साथ एकीकृत करके भंडारण सुविधाओं तक किसानों की सीधी पहुंच सुनिश्चित करेगी जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता नहीं रह जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, परिवहन लागत कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना है। गांवों में भंडारण और कृषि संबंधी अन्य सुविधाएं विकसित होने से सहकारी क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी जिससे विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

अभी देश में करीब 33 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। इसके मुकाबले अनाज भंडारण की क्षमता आधे से भी कम करीब 14.5 करोड़ टन ही है। देश के 26 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 430 जिलों में भंडारण की भारी कमी है, जिससे वहां के किसानों को भंडारण संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की आवश्यकता के बराबर भी अनाज का भंडारण नहीं होता है, जबकि खाद्यान्न की पैदावार कुल जरूरत के मुकाबले अधिक है। खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में भंडारण की भारी कमी है, जबकि मध्य प्रदेश और हरियाणा में स्थिति संतोषजनक है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य भी भंडारण की कमी से जूझ रहे हैं। पैक्स के स्तर पर अनाज भंडारण के सक्षम हो जाने से फसल कटाई के बाद अनाज की बबार्दी रोकने और कीटों के कारण उन्हें खराब होने से रोकने में मदद मिलेगी। भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था हो जाने से किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचने से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जिन अनाजों का भंडारण किया जाता है उन्हें पहले गांव के खेत से ले जाकर शहर स्थित गोदामों में रखा जाता है और फिर वहां से गांव स्थित राशन की दुकानों तक पहुंचाया जाता है। इससे परिवहन लागत दोगुनी हो जाती है। स्थानीय स्तर पर भंडारण की व्यवस्था हो जाने से परिवहन लागत कम होगी और ग्रामीणों की खाद्यान्न तक पहुंच आसान होगी। इससे बिचौलियों पर भी निर्भरता घटेगी और किसानों की बाजार बढ़ेगी। यह योजना कृषि उपज के मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा देगी जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

ऑपरेशन सिंदूरः आतंक पर कड़ा प्रहार

युवा सहकार टीम

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए जघन्य आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से देश के जनमानस में उबाल था उससे यह अंदाजा तो सहज ही लगाया जा रहा था कि भारत पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मगर इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई का अनुमान शायद ही किसी ने लगाया होगा जो एक तरह से छोटे युद्ध जैसा था। 1971 के बाद यह पहली बार था जब आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूत करने के लिए भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान की धरती पर हमला किया था। हालांकि, इससे पहले उरी और पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया था लेकिन वह पाक कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में मौजूद आतंकी ठिकानों तक ही सीमित था।

22 अप्रैल को बैसरन घाटी में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के एक समूह ने 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी। इस हमले में आतंकवादियों ने एक खास तरीका अपनाया था जिसका मकसद भारत की धर्मनिरपेक्ष आत्मा पर भी चोट करना था। आतंकवादियों ने केवल पुरुषों को गोली मारी। उससे पहले हत्यारों ने उनका धर्म भी पूछा। 1990 के दशक में जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए व्यापक हमलों के बाद शायद यह पहला मौका था जब आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को अपना निशाना बनाया। इस हमले की पूरी दुनिया ने कड़ी निंदा की। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरआफ) ने ली जो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का ही एक संगठन है। लश्कर का मुखिया हाफिज सईद है। इसके अलावा, मसूद अजहर के नेतृत्व वाला जैश-ए-मोहम्मद भी पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां चलाता है।

पीओके और पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को भारत ने किया नेस्तनाबूत, कई एयरबेस भी किए तबाह

इस कायरतापूर्ण हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंक के आकाओं और पनाहगारों को कड़ी चेतावनी देते हुए आगाह कर दिया था कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सिंधु जल संधि समझौते समेत भारत सरकार ने कई कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाये। साथ ही सरकार ने सेना को भी खुली छूट देते हुए कहा कि आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जगह और समय वह तय करे। 6 मई को आधी रात के बाद पीओके और पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया गया। इन ठिकानों पर ही आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और बाद में भारत भेज कर हमले करवाए जाते थे। इस हमले में बहावलपुर स्थित जैश का मुख्यालय और मुरीदके स्थित लश्कर का मुख्यालय पूरी तरह से तबाह हो गया। इस हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया कि उसका निशाना पाकिस्तान नहीं, बल्कि आतंकवाद और आतंकी हैं। मगर पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारत के सीमावर्ती राज्यों के कई शहरों में मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया जिसका भारतीय सैन्य बलों ने करारा जवाब देते हुए उन्हें हवा में ही मार गिराया। इसके बाद भारत की ओर से किए गए जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह होने की खबर है। इसमें रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस भी शामिल है। यह एयरबेस पाकिस्तान के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इसी एयरबेस के पास पाकिस्तान का परमाणु हथियार मौजूद है।

भारत के इस कड़े प्रहार से पाकिस्तान की कमर टूट गई और उसे समझ में आ गया कि अगर हमला बंद नहीं हुआ तो पूर्ण युद्ध शुरू हो जाएगा जिसमें उसकी पूरी तबाही निश्चित है। सैन्य और आर्थिक दोनों रूप से पाकिस्तान भारत से पूर्ण युद्ध करने में सक्षम नहीं है। इसलिए उसने सीजफायर की गुहार लगाई जिसे भारत ने मान लिया। हालांकि, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी सिर्फ स्थगित किया गया है, बंद नहीं। ■

अन्न भंडारण योजना

ग्रामीण युवाओं के रोजगार का नया अवसर

देश के कोने-कोने में पैक्स के माध्यम से हजारों गोदाम बनाने की तैयारी

पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों में बने गोदाम में शुरू हुआ अनाज भंडारण

500 अन्य पैक्स में गोदाम निर्माण का चल रहा कार्य

विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर आएगी एक लाख करोड़ रुपये की लागत

युवा सहकार टीम

विश्व की सबसे बड़ी आबादी का पेट भरने और पुख्ता खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जहां खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्पादकता पर जोर दे रही है, वहीं उपज के सुरक्षित भंडारण को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री अन्न भंडारण योजना की शुरूआत की गई है। इसके तहत पैक्स के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में अनाज के गोदाम बनाए जा रहे हैं। इस योजना से न सिर्फ गांवों में ही अनाज भंडारण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। इसके अलावा, भंडारण के दौरान अनाज की होने वाली क्षति को भी रोका जा सकेगा। गांव में

गोदाम बनेगा तो उनका रखरखाव, प्रबंधन करने जैसे प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा अनाजों की ढुलाई सहित अन्य अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे जो निश्चित तौर पर उस गांव और पंचायत के युवाओं के लिए ही उपलब्ध होंगे जहां यह बनेगा। इसके साथ ही कृषि और उससे संबंधित अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी निर्माण होगा जिसमें भी रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पांच वर्ष में कुल सात करोड़ टन खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। इसमें सबसे अहम भूमिका सहकारी क्षेत्र की निचली इकाई पैक्स की है। पैक्स को कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने, किसानों से अनाज की खरीद करने, मंडियों से अनाज खरीद के बाद उसकी प्राथमिक प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने और खाद्यान्न के भंडारण की क्षमता विकसित करने के लिए नामित किया गया है। योजना को देश भर में लागू करने के पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुल 24 राज्यों के 24 जिलों की कुल 24 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का चयन किया गया है। इनमें से 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदाम

33.09
करोड़ टन खाद्यान्न का कुल उत्पादन

14.5
करोड़ टन ही है भंडारण क्षमता

18.59
करोड़ टन भंडारण क्षमता की कमी

देश की प्रमुख भंडारण एजेंसियां

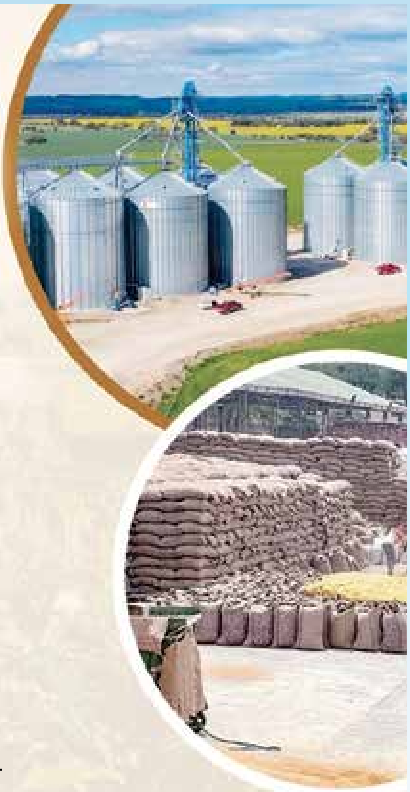

- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)
- केंद्रीय भंडारागार निगम (सीडब्लूसी)
- वेयरहाऊसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्लूडीआरए)
- स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन (एसडब्लूसी)
- रेलवे भंडारागार निगम के गोदाम
- राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग के गोदाम
- निजी और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के गोदाम

ग्राम पंचायत स्तर पर अनाज की जरूरत के हिसाब से 50, 100, 250, 500 और 750 टन क्षमता के साइलोज (आधुनिक तकनीक से स्टील के गोदाम) और सामान्य गोदाम बनाए जा रहे हैं। पैक्स के बनाए इन गोदामों को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य प्राइवेट एजेंसियों को भंडारण के लिए किराये पर दिया जाएगा।

का निर्माण कर उनमें भंडारण शुरू किया जा चुका है। इनका निर्माण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) के सहयोग से किया गया है। इन 11 राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा और राजस्थान के 11 पैक्स शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर कुल 9,750 टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से उत्साहित होकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने विस्तारित पायलट के तहत भाग लेने के लिए 575 अतिरिक्त पैक्स की पहचान की। इनमें से 500 पैक्स में गोदाम के निर्माण के लिए शिलान्यास किया जा चुका है। 326 पैक्स के डीपीआर प्रस्तुत किए गए हैं और 136 पैक्स का वित्तीय समापन पूरा हो चुका है। इन गोदामों की क्षमता उपयोग के लिए एफसीआई, एनसीडीसी और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) हो चुका है।

अनुमान है कि 2047 तक भारत की आबादी लगभग 1.61 अरब हो जाएगी जिसके लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ खाद्यान्न भंडारण के बुनियादी ढांचे में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी। यह परियोजना जमीनी स्तर पर भंडारण क्षमता को बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देगी। यह पैक्स को भी मजबूत करेगा, फार्मगेट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा और किसानों की आय बढ़ाएगा। समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी जिससे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।

सभी ब्लॉकों में बनेंगे गोदाम

ग्रामीण गोदामों के निर्माण के पहले चरण में देश के सभी ब्लॉकों में गोदाम बनाए जाएंगे। इस हिसाब से तकरीबन 50,000 टन गोदामों का निर्माण पहले चरण में होने का अनुमान है। इस योजना में नई फ्लेक्सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर अनाज की जरूरत के हिसाब से 50, 100, 250, 500 और 750 टन क्षमता के साइलोज (आधुनिक तकनीक से स्टील के गोदाम) और सामान्य गोदाम बनाए जा रहे हैं। पैक्स के बनाए इन गोदामों को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य प्राइवेट एजेंसियों को भंडारण के लिए किराये पर दिया जाएगा। इससे पैक्स की आमदनी बढ़ेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पैक्स के खरीदे अनाज की बिक्री की जा सकेगी। इन गोदामों में अनाज की प्रोसेसिंग की भी सुविधा होगी, जिससे उपज को मूल्यवर्धित करके बेचा जा सकेगा। ग्राम स्तर पर बनाए जाने वाले छोटे गोदामों से

किसानों को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा, सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज को राशन की दुकानों तक पहुंचाने का खर्च भी कम होगा। अभी होता यह है कि गांव से अनाज शहर के गोदामों तक पहुंचता है और वहां से फिर गांव के राशन दुकानों तक पहुंचाया जाता है। इससे माल ढुलाई का खर्च दोगुना हो जाता है। गांव में जब गोदाम बन जाएंगे तो अनाजों को राशन की दुकानों तक पहुंचाने के खर्च में काफी कमी आएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार, आगामी पांच वर्षों में देश में खाद्यान्न भंडारण की क्षमता सात करोड़ टन तक हो जाएगी। इससे देश में खाद्यान्न की बबार्दी रोकने में मदद मिलेगी। इस दिशा में सहकारिता क्षेत्र से और अधिक अपेक्षाएं हैं। सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि यह एक भावना और चेतना है। सहकारिता जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को एक बड़ी औद्योगिक शक्ति में बदल सकती है। यह देश की अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में अन्न भंडारण योजना बड़ा कदम है। इसके तहत देश में कोने-कोने में हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। ये सभी काम कृषि के बुनियादी ढांचे को विस्तार देने में सहायक होंगे और उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे।

आधे से भी कम अनाजों का भंडारण

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान में फसल वर्ष 2024-25 में 33.09 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। भारत में खाद्यान्न भंडारण की कुल क्षमता केवल 14.49 करोड़ टन यानी करीब 47 प्रतिशत है, जबकि अन्य देशों में भंडारण क्षमता उत्पादन के मुकाबले 131 प्रतिशत तक है। वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न उत्पादक देशों में उत्पादन के मुकाबले भंडारण क्षमता अधिक है। देश में गोदामों की कम संख्या और अपर्याप्त भंडारण क्षमता की वजह से खाद्यान्न की बबार्दी होती है और किसानों पर अपने उपज के गैर-लाभकारी मूल्यों पर बेचने का दबाव भी रहता है। वैश्विक स्तर पर चीन में खाद्यान्न उत्पादन 61.5 करोड़ टन के मुकाबले भंडारण क्षमता 66 करोड़ टन है और अमेरिका में 42.2 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन के मुकाबले 68 करोड़ टन की भंडारण क्षमता है। ब्राजील, रूस, अर्जेंटीना, यूक्रेन, फ्रांस और कनाडा में भी खाद्यान्न

सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में अन्न भंडारण योजना बड़ा कदम है। इसके तहत देश में कोने-कोने में हजारों गोदाम बनाए जाएंगे।

430 जिलों में अन्न भंडारण की भारी कमी

देश के 26 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 430 जिलों में भंडारण की भारी कमी है, जिससे वहां के किसानों की मुश्किलें अधिक हैं। इन जिलों में लगभग 74,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। इन जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की आवश्यकता के बराबर भी अनाज का भंडारण नहीं होता है। जबकि इन जिलों में खाद्यान्न की पैदावार यहां कुल जरूरत के मुकाबले अधिक (सरप्लस) होती है। हालांकि देश में कुल पांच राज्यों के 134 जिलों में से नौ जिले ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त भंडारण क्षमता (सरप्लस) है।

खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में पंजाब एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से मात्र एक जिले में भंडारण की कमी है। इसी तरह हरियाणा के तीन जिलों में भंडारण की कमी है। जबकि पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से 22 जिले और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 64 जिलों में भंडारण की भारी कमी है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में खाद्यान्न भंडारण की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

एनबीसीसी सहकारिता क्षेत्र की निचली इकाई प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) के साथ मिलकर ग्रामीण भंडार गृहों का निर्माण कर रही है। सहकारिता मंत्रालय की देखरेख में एनबीसीसी ने अब तक दो सौ से अधिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) कर लिया है।

उत्पादन के मुकाबले उनकी अन्न भंडारण क्षमता अधिक है। इनके मुकाबले भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में करीब 18 करोड़ टन खाद्यान्न भंडारण की कमी है।

खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद होने से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, जिसमें पैक्स, निजी क्षेत्र और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) जैसी सरकारी एजेंसी शामिल होगी। स्थानीय स्तर पर सरकारी खरीद होने से स्थानीय जरूरतें भी वहीं से पूरी की जा सकेंगी। आसपास की मंडियों और रियायती दर की राशन दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए कम लागत में खाद्यान्न की सप्लाई की जा सकेगी। इससे जहां एक ओर महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी, वहीं सरकारी खजाने पर खाद्य सब्सिडी का बोझ भी घटेगा। पैक्स के स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाने से उपज बढ़ाने और फसल की बबार्दी को रोकने में सहायता मिलेगी। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष और कृषि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना में पैक्स को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इससे गोदामों में अनाज के भंडारण से पहले अनाज की सफाई, अनाज की छंटाई और अनाज को सुखाने जैसे उपकरणों की खरीद की जा सकेगी। इससे भी रोजगार बढ़ेगा।

एनबीसीसी गोदाम निर्माण की नोडल एजेंसी

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और सहकारिता मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के समन्वय से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना लागू की जा रही है। पूरी योजना के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सौंपा गया है। पीएम अन्न भंडारण योजना में अपनी भागीदारी को लेकर राज्यों ने उत्साह दिखाना शुरू कर दिया है। सहकारी क्षेत्र की संस्था भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नैफेड) ने आगे बढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय निर्माण एजेंसी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। एनबीसीसी सहकारिता क्षेत्र की निचली इकाई प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) के साथ मिलकर ग्रामीण भंडार गृहों का निर्माण कर रही है। सहकारिता मंत्रालय की देखरेख में एनबीसीसी ने अब तक दो सौ से अधिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) कर लिया है।

दाल व सब्जियों के भी गोदाम

सहकारिता क्षेत्र की एजेंसी एनसीसीएफ दाल और सब्जियों के भंडारण के लिए अलग-अलग उत्पादक राज्यों में गोदाम बनाने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। इसी तरह नैफेड ने भी अपने उत्पादक केंद्रों एवं मंडियों

अन्न भंडारण योजना के लाभ

- **फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी:** उचित विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाओं से फसल कटाई के बाद खराब होने और कीटों के कारण अनाज की बबार्दी रोकने में मिलेगी।
- **खाद्य सुरक्षा में वृद्धि:** भंडारण में वृद्धि से स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- **किसानों की आय में वृद्धि:** किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे और दबाव में कम कीमत पर बेचने की बजाय उचित समय पर बेहतर कीमत पर बेच सकेंगे।
- **पैक्स के गोदामों को खरीद केंद्र और राशन दुकान के रूप में मिलेगी मान्यता:** खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) में स्वीकृत पैक्स को अनाज खरीद केंद्र और उचित मूल्य की दुकान दोनों के रूप में मान्यता देने के आदेश जारी किए हैं। इससे परिवहन लागत कम होगी और ग्रामीण नागरिकों की खाद्यान्न तक पहुंच आसान होगी।
- **सहकारी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** पैक्स इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक स्तर पर सहकारी संरचना मजबूत होगी।
- **बेहतर आपूर्ति श्रृंखला दक्षता:** सुव्यवस्थित भंडारण और वितरण से बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और बाजार पहुंच में सुधार होगा।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** इस योजना से कृषि उपज के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- **रोजगार के नए अवसर:** ग्रामीण इलाकों में गोदामों के निर्माण एवं कृषि संबंधी अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

में पैक्स के साथ मिलकर गोदाम बनाने का फैसला किया है। इससे पैक्स को एक सुनिश्चित आमदनी की गारंटी प्राप्त हो जाएगी। विभिन्न राज्यों में एनसीसीएफ और नैफेड ने 2,500 से अधिक पैक्स को चिन्हित किया है, जहां गोदाम बनाए जा सकते हैं। सब्जियों के गोदाम बनने से इसकी खेती को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। पारंपरिक फसलों की तुलना में सब्जी की खेती से ज्यादा आमदनी होती है। इसलिए युवा किसान इस ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि, सब्जी भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से सब्जी उत्पादकों को कई बार भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था हो जाने से न सिर्फ आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकेगा, बल्कि सब्जियों की बबार्दी भी रुकेगी। सहकारिता मंत्रालय की एक सूचना के मुताबिक, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य अपने यहां पैक्स के साथ बनाए जाने वाले गोदामों का निर्माण राज्य एजेंसियों

स्रोतः सहकारिता मंत्रालय

पीएम अन्न भंडारण योजना से पैक्स से जुड़े तकरीबन 13 करोड़ किसानों का लाभ होगा। सहकारी क्षेत्र से जुड़े इन किसानों को खेती के इनपुट खाद, बीज व कीटनाशक समेत अन्य वस्तुओं की आपूर्ति सहकारी संस्थाओं से होती है। देश के सभी पैक्स को 352 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों और 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों से तकरीबन पांच लाख करोड़ रुपये का सालाना ऋण वितरित किया जाता है। इसमें 1.3 लाख करोड़ रुपये नाबार्ड द्वारा री-फाइनेंस किया जाता है।

से कराना चाहते हैं। उन्हें इसकी अनुमित दे दी गई है।

पीएम अन्न भंडारण योजना से पैक्स से जुड़े तकरीबन 13 करोड़ किसानों का लाभ होगा। सहकारी क्षेत्र से जुड़े इन किसानों को खेती के इनपुट खाद, बीज व कीटनाशक समेत अन्य वस्तुओं की आपूर्ति सहकारी संस्थाओं से होती है। देश के सभी पैक्स को 352 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों और 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों से तकरीबन पांच लाख करोड़ रुपये का सालाना ऋण वितरित किया जाता है। इसमें 1.3 लाख करोड़ रुपये नाबार्ड द्वारा री-फाइनेंस किया जाता है।

देश में खाद्यान्न भंडारण की कमी से देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों को भारी क्षति हुई है। भारत जितना अनाज पैदा करता है, उसका 50 प्रतिशत से भी कम भंडारण कर पाता है। दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना से देश के किसानों का सामर्थ्य बढ़ेगा और गांवों में नए रोजगार पैदा होंगे। गांवों में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा सहकारी समितियों (पैक्स) का है। फार्मगेट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्थाओं के निर्माण में सहकारी सेक्टर को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। नए भारत में सहकारिता देश की आर्थिक धारा का सशक्त माध्यम बनेगी। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाली है, जो किसानों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लचीलापन, दक्षता और समृद्धि सुनिश्चित करेगी। सरकार का प्रयास ऐसे गांवों के निर्माण की तरफ भी बढ़ना है, जो सहकारिता के मॉडल पर चलकर आत्मनिर्भर बनें। ■

डिपो दर्पण से होगी खाद्यान्न भंडारण की सटीक निगरानी

युवा सहकार टीम

देशभर में मौजूद खाद्यान्न भंडारण डिपो में वैज्ञानिक और स्मार्ट भंडारण समाधान के लिए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग लगातार आधुनिक तरीके अपना रहा है। इसी सिलसिले में भंडारण व्यवस्था की सटीक निगरानी रखने के लिए इसे डिजिटल स्वरूप देने के तहत डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य भंडारण डिपो उच्चतम गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को पूरा करें। यह डिपो प्रबंधकों को वास्तविक समय के आधार पर बुनियादी ढांचे, परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएगा।

डिपो दर्पण को स्मार्ट वेयरहाउसिंग टेक्नोलॉजी के साथ विशिष्ट रूप से एकीकृत किया गया है जिससे एक निर्बाध डिजिटल निगरानी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है। इसमें सीसीटीवी से निगरानी और आईओटी सेंसर जैसे प्रमुख मापदंडों को शामिल किया गया है जिससे खाद्यान्न भंडारण में सुरक्षा और दक्षता दोनों सुनिश्चित होगी। आईओटी सेंसर के तहत गोदामों में परिवेश सेंसर, सीओ2 और फॉस्फीन सेंसर, आग सेंसर और शटर गेट सेंसर लगाया गया है। परिवेश सेंसर से अनाज की नमी और तापमान की निगरानी की जाएगी, जबकि सीओ2 सेंसर से अनाज के संभावित संक्रमण की निगरानी की जा सकेगी और फॉस्फीन गैस सेंसर विषाक्त गैस की पूर्व चेतावनी देगा। इसी तरह, तय समय के बाद गोदामों के दरवाजे खुलने की स्थित में गेट शटर सेंसर अलर्ट कर देगा जिसे अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सकेगा। गोदाम में आग लगने की स्थित में अग्नि सेंसर तुरंत अलर्ट जारी करेगा जिससे आग से होने वाले नुकसान को तुरंत रोका जा सकेगा।

इसके अलावा अनाजों की बोरियां गिनने के लिए एआई आधारित तकनीक, खाद्यान्न लाने एवं ले जाने वाले वाहनों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए एएनपीआर (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान) और प्रवेश नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक (एफआरएस) को भी पायलट आधार पर गोदामों में तैनात किया गया है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं केंद्रीय भंडारागार निगम (सीडब्ल्यूसी) के स्वामित्व वाले तथा राज्य एजेंसियों एवं निजी क्षेत्र से किराये पर लिए गए गोदामों सहित कुल 2,278 गोदाम इस डिजिटल पहल में शामिल किए गए हैं।

डिपो दर्पण के माध्यम से डिपो प्रबंधक अपने डिपो में उपलब्ध बुनियादी ढांचे के जियो टैग किए गए इनपुट को अपलोड करेंगे जिससे समय पर सुधार के लिए स्वचालित रेटिंग और एक्शन प्वाइंट तैयार हो जाएगा। इसके माध्यम से न सिर्फ डिपो प्रबंधक, बल्कि पर्यवेक्षी अधिकारी और तीसरे पक्ष के ऑडिटर भी किसी भी समय, कहीं से भी भंडार के प्रदर्शन को ट्रैक कर सकेंगे जिससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। स्वचालित रिपोर्ट का उपयोग नियमित समीक्षाओं में किया जा सकेगा जिससे बुनियादी ढांचे और दक्षता में निरंतर और निर्बाध सुधार होता रहेगा।

इसमें शामिल गोदामों का मूल्यांकन दो श्रेणियों के आधार पर किया जाएगा। पहला, इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी पहलू जिनमें सुरक्षा मानक, भंडारण की स्थिति, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और वैधानिक मापदंड शामिल हैं। दूसरा है परिचालन दक्षता पहलू जिसमें स्टॉक टर्नओवर, घाटा, स्थान उपयोग, जनशक्ति व्यय और लाभप्रदता शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से किया जाएगा तथा गोदाम को दोनों मापदंडों के समग्र स्कोरिंग के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएंगी। ■

सहकारी डेयरी का विस्तार, बढ़ेगा ग्रामीण रोजगार

युवा सहकार टीम

मध्य प्रदेश के दूध उत्पादन में सहकारी डेयरी समितियों का योगदान बढ़ाने के लिए एमपीसीडीएफ का एनडीडीबी से अनुबंध

गांवों में सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति स्थापित होने से बढ़ेगी मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता, किसान होंगे समृद्ध

मध्य प्रदेश के दूध उत्पादन में सहकारी डेयरी समितियों का योगदान बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से अनुबंध (एमओयू) किया है। इसके तहत राज्य के हर गांव तक सहकारी डेयरी का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए फाइनेंस की जरूरत को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) पूरा करेगा। इससे न सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार का नया विकल्प भी तैयार हो सकेगा। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।

इस अवसर पर अमित शाह ने कहा, 'अभी मध्य प्रदेश में साढ़े पांच करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो देश के कुल दूध उत्पादन का 9 प्रतिशत है। इसमें सहकारी डेयरियों का हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम है। इस अनुबंध से राज्य के कुल दूध उत्पादन में सहकारी डेयरियों की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य का सरपल्स दूध साढ़े तीन करोड़ लीटर है। इनमें से 2.5 प्रतिशत ही सहकारी डेयरी के पास आता है। अभी यहां केवल 17 प्रतिशत गांवों में ही दूध संग्रह की व्यवस्था है। इस अनुबंध से 83 प्रतिशत गांवों तक सहकारी डेयरी के विस्तार की संभावना बन गई है।' शहरों में दूध की मांग 1.20 करोड़ लीटर प्रतिदिन है, जिस पर किसान को ठीक से मुनाफा नहीं मिलता। इस अनुबंध के तहत सहकारिता मंत्री ने शुरूआती पांच साल में 50 प्रतिशत गांव में सहकारी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति की स्थापना का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। अगर 50 प्रतिशत गांव में सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति स्थापित हो गई, तो सहकारी क्षेत्र में मिल्क प्रोसेसिंग की क्षमता कई गुणा बढ़ जाएगी। इससे किसान भी समृद्ध होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब किसान अपना

दूध खुले बाजार में बेचने जाता है तो उसका शोषण होता है। हमारा लक्ष्य है कि तेजी से हर गांव के किसान को सहकारी डेयरी से जोड़ा जाए। साथ ही, ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि दूध से पनीर, दही, छाछ, मट्ठा आदि बनाकर बेचा जाए और मुनाफा किसान को मिले। मध्य प्रदेश को आने वाले दिनों में प्राथमिक डेयरी का विस्तार करना है, दूध का कलेक्शन बढ़ाना है, पशुओं को अच्छा चारा उपलब्ध कराना है, उनकी ब्रीड सुधारनी है ताकि हर पशु ज्यादा दूध दे। दूध को प्रोसेस करके ज्यादा मुनाफे के साथ बेचने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाना है। सहकारिता मंत्री के अनुसार, गुणवत्ता की जांच और किसानों को हर सप्ताह भुगतान सुनिश्चित हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन को नीति निर्माण और ब्रांडिंग का काम करना होगा। एनडीडीबी और एमपीसीडीएफ को आक्रमक तरीके से काम करना चाहिए ताकि कम से कम 50 प्रतिशत गांवों में डेयरी पहुंचे और किसानों को इसका फायदा हो।

उन्होंने कहा कि किसानों को उसके दूध उत्पादन का शत प्रतिशत फायदा मिलना चाहिए, तभी दूध का उत्पादन बढ़ सकेगा। मोदी सरकार मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर राज्य के किसानों की भलाई के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए कटिबद्ध है। सहकारी क्षेत्र को जीवित करने का यह स्वर्णिम अवसर है। मध्य प्रदेश को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। राज्य में कृषि, पशुपालन और सहकारिता, तीनों क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं मौजूद हैं। इनका शत-प्रतिशत दोहन करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत है।

सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। अब यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने पैक्स को पुनर्जीवित करने, डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाने, शहरी सहकारी बैंकों, जिला सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों के सुचारू संचालन की दिशा में प्रयास किए हैं।

सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहले पैक्स के लिए मॉडल बायलॉज बनाने का काम किया और राज्य सरकारों को इसे स्वीकृति के लिए भेजा। सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया है। इस कदम से सहकारिता क्षेत्र में नई जान आई है। जब तक पैक्स मजबूत नहीं होती, तब तक तीन स्तरीय सहकारी खाका मजबूत नहीं हो सकता। पहले पैक्स सिर्फ लघु अवधि के कृषि ऋण देने का काम करते थे जिससे उनकी आय कम होती थी। आज पैक्स 20 से अधिक प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नए सुधारों से पैक्स की आय बढ़ रही है। पैक्स को जन औषधि केंद्र, जल वितरण, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। ■

शुरूआती पांच साल में 50 प्रतिशत गांव में सहकारी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति की स्थापना का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। अगर 50 प्रतिशत गांव में सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति स्थापित हो गई, तो सहकारी क्षेत्र में मिल्क प्रोसेसिंग की क्षमता कई गुणा बढ़ जाएगी।

युवाओं और सहकारिता का भविष्य संवारेगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय

दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, एनसीयूआई और इफको

भारत में सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय' की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। संसद के दोनों सदनों से त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 के पारित होने के साथ ही अब यह सपना साकार होने जा रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना से न केवल सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सहकारी क्षेत्र को अधिक पेशेवर और प्रभावी बनाने में भी यह मदद करेगा। सहकारी आंदोलन के लिए यह ऐतिहासिक कदम साबित होगा। यह संस्थान सहकारी शिक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जिससे सहकारी संस्थानों का कार्य अधिक पेशेवर, आधुनिक और प्रभावी हो सकेगा। यह युवाओं को एक वैकल्पिक और आकर्षक करियर विकल्प प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को सहकारी संस्थाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे यह एक आकर्षक करियर विकल्प बनेगा।

सहकारी क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा देकर यह विश्वविद्यालय युवाओं को सहकारी प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, सहकारी विपणन, डिजिटल सहकारिता और अन्य विषयों में विशेष शिक्षा प्रदान करेगा। पेशेवर प्रशिक्षण और नवीनतम शोध के माध्यम से सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा। डिजिटल तकनीकों, डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से सहकारी संस्थानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी कर भारतीय सहकारी क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा।

भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इसके विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। सहकारी संस्थाएं अक्सर पेशेवर प्रबंधन की कमी, नवीनतम तकनीकों की अनुपस्थिति और प्रभावी नेतृत्व के अभाव में संघर्ष करती रही हैं। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय इन सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा और सहकारी क्षेत्र को एक स्वर्णिम युग में प्रवेश करने में सहायता करेगा।

भारत में सहकारी आंदोलन की शुरूआत औपनिवेशिक काल में हुई थी। 1904 में सहकारी समितियों से संबंधित पहला कानून लाया गया जिसके बाद इस आंदोलन को एक संरचित रूप मिला। आज भारत में सहकारी समितियां कृषि, बैंकिंग, डेयरी, आवास, उपभोक्ता वस्तुएं और अन्य कई क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अमूल, इफको, कृभको जैसी संस्थाएं सहकारी आंदोलन के सफल उदाहरण हैं। हालांकि, सहकारी क्षेत्र की बढ़ती चुनौतियां, जैसे डिजिटल तकनीक का अभाव, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना और व्यावसायिक कौशल की कमी, इसके सतत विकास में बाधा बन रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

युवाओं के करियर का नया विकल्प

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला पहला संस्थान होगा। इसके पाठ्यक्रम विशेष रूप से व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख होंगे। इन पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:

1. **सहकारी प्रबंधन:** इसके तहत सहकारी संस्थानों के सुचारू संचालन और नेतृत्व कौशल की शिक्षा दी जाएगी।

2. सहकारी वित्तः सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में काम करने के लिए पेशेवर ट्रेनिंग दी जाएगी।

3. डिजिटल सहकारिताः सहकारी क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल को कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि समावेशिता को बढ़ावा मिल सके, इस बारे में पढ़ाया जाएगा।

4. सामुदायिक विकास और सहकारिताः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने की शिक्षा इसके तहत दी जाएगी।

5. कृषि और ग्रामीण सहकारिताः कृषि आधारित सहकारी समितियों को आधुनिक बनाने के बारे में युवाओं को शिक्षित किया जाएगा।

इस विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले छात्रों को सहकारी संस्थाओं में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि यह एक आकर्षक करियर विकल्प बन सके।

शोध और प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण

सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए शोध और प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। इसके लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देगाः

1. सहकारी नीतियों पर शोधः विभिन्न देशों और राज्यों की सहकारी नीतियों पर शोध को बढ़ावा देकर भारत के लिए उपयुक्त सहकारी नीतियों का विकास किया जाएगा।

2. प्रशिक्षण कार्यशालाएंः सहकारी क्षेत्र के कार्यकताओं और प्रबंधकों के लिए समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

3. नवाचार एवं तकनीकी समावेशनः सहकारी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग को बढ़ावा देने के उपाय किए जाएंगे।

सहकारी आंदोलन और 'विकसित भारत' का लक्ष्य

भारत सरकार 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। सहकारी क्षेत्र इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित तरीकों से योगदान देगाः

आत्मनिर्भर भारतः सहकारी समितियां स्थानीय स्तर पर उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी।

रोजगार सृजनः सहकारी क्षेत्र के विस्तार से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

कृषि क्षेत्र में क्रांतिः कृषि सहकारी समितियों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाई जाएगी।

वित्तीय समावेशनः सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटीज ग्रामीण भारत को वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगी।

स्थानीय से वैश्विकः त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय भारतीय सहकारी संगठनों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना सकें।

हरित और सतत विकासः सहकारी संगठनों को पर्यावरण अनुकूल नीतियों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे सतत विकास को बल मिलेगा।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय देश में सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक सहकारी संगठनों के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत करेगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रभावी भूमिका निभाएगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जा रही हैः

1. युवाओं के लिए रोजगारपरक शिक्षाः सहकारी क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा की कमी के कारण युवा इस क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते। यह विश्वविद्यालय युवाओं को सहकारी प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, सहकारी विपणन, डिजिटल सहकारिता और अन्य विषयों में विशेष शिक्षा प्रदान करेगा।

2. सहकारी संगठनों का सशक्तीकरणः यह विश्वविद्यालय पेशेवर प्रशिक्षण और नवीनतम शोध के माध्यम से सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा।

3. डिजिटल युग में सहकारी आंदोलन का विकासः देश के ज्यादातर सहकारी संस्थानों में वर्तमान में डिजिटल तकनीकों, डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग की कमी है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय इन कमियों को पूरा करने के साथ-साथ सहकारी संस्थानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने में मदद करेगा।

4. ग्लोबल कोऑपरेटिव नेटवर्किंगः गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा) में बनने वाला यह विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी कर भारतीय सहकारी क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा।

अंत्योदय से विकसित भारत

राजेश पांडे

महामंत्री, महाराष्ट्र भाजपा

पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के एक तपस्वी, तेजस्वी और ऋषितुल्य व्यक्तित्व थे। उनका जीवन केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्र के उत्थान को समर्पित था। उन्होंने भारतीय राजनीति को 'एकात्म मानवदर्शन' और 'अंत्योदय' जैसी विचारधाराओं के माध्यम से एक नई वैचारिक दिशा दी। वर्ष 1965 में 22-25 अप्रैल के दौरान मुंबई के माटुंगा स्थित रामनारायण रुईया महाविद्यालय में उन्होंने 'एकात्म मानवदर्शन' और 'अंत्योदय' की ऐतिहासिक प्रस्तुति दी थी। इस ऐतिहासिक प्रस्तुति की 60वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई जा रही है जो भारत की वैचारिक साधना को अधिक समृद्ध बनाने में मददगार होगी।

पंडितजी का 'एकात्म मानवदर्शन' समाज के अंतिम व्यक्ति को केंद्र में रखकर विकास की दिशा तय करता है। उनका मानना था कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक जीवंत राष्ट्र है। 'भारत माता' है, जो अपने नागरिकों में देशभक्ति, त्याग और कर्तव्यबोध जागृत करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इसी मूल विचारधारा पर आधारित है। पार्टी का प्रत्येक निर्णय भारत माता के कल्याण के लिए हृदय से समर्पित होता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' के सपने को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। 'जनधन योजना' के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। 'डीबीटी' यानी

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसे पहुंचा कर भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया। 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई मिली। 'पीएम किसान सम्मान निधि', 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'मातृ वंदना योजना', 'विश्वकर्मा योजना', 'स्टार्टअप इंडिया', 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया' जैसी अनेक योजनाओं ने आम जनजीवन को सशक्त किया है। महिला, युवा, गरीब और किसान ही इन योजनाओं के केंद्र में हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' विचार को भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक नींव में आत्मसात किया है। उन्होंने भाजपा को एक राष्ट्रवादी विचारधारा के मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा किया, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का संकल्प प्रमुख है। श्री शाह के संगठनात्मक कौशल और दूरदर्शिता ने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बना दिया है।

महाराष्ट्र में भी भाजपा प्रणीत महायुती सरकार मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 'जलयुक्त शिवार', 'नमो शेतकरी सन्मान निधि', 'लाडकी लेक योजना', 'मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना', 'महिला सम्मान योजना', 'अटल कामगार योजना' जैसी कई अभिनव योजनाओं के माध्यम से गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बना रही है। साथ ही, सरकार के प्रयासों से राज्य में बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इससे गांव और शहर के बीच का फासला कम हो रहा है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' की संकल्पना आज हर नीति और हर योजना में परिलक्षित होती है। 'स्वच्छ भारत अभियान', 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम', 'शासन आपल्या दारी' जैसी योजनाओं ने आमजन तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित की है। महाराष्ट्र ने 'सेल्फी विद मेरी माटी' (#SelfieWithMeriMaati) अभियान में 10 लाख से अधिक सेल्फियों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर देशभक्ति की भावना का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आत्मसात करते हुए समर्पण और सेवा भाव से कार्य कर रहा है। पार्टी का मानना है कि विकास केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया है।

आज जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है, तब यह कहा जा सकता है कि यह यात्रा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि आत्मिक, नैतिक और सामाजिक रूप से समृद्ध राष्ट्र निर्माण की ओर है। यही अंत्योदय के माध्यम से विकसित भारत की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा, जिसमें हर भारतीय की भागीदारी हो और जिसका प्रत्येक कदम राष्ट्रहित की दिशा में हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'अंत्योदय' और 'एकात्म मानववाद' की संकल्पना आज भारतीय जनता पार्टी के शासन और सेवा के मूल में जीवित है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचता, तब तक राष्ट्र की प्रगति अधूरी है, यह भाजपा की स्पष्ट नीति और निष्ठा है। यही भारत माता को समर्पित भाजपा का ध्येय है: राष्ट्र प्रथम, अंतिम व्यक्ति सर्वोपरि।

जब समाज का अंतिम व्यक्ति सशक्त होता है, तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। यही है 'विकसित भारत' की असली परिभाषा: एक ऐसा भारत, जो न केवल भौतिक रूप से, बल्कि वैचारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वैचारिक साधना को नमन और उनके 'अंत्योदय' स्वप्न को साकार करने में जुटे हर कार्यकर्ता को राष्ट्र निर्माण की इस पुण्य यात्रा के लिए शुभकामनाएं। भाजपा का यह संकल्प है: 'अंत्योदय से विकसित भारत', जिसके लिए जीने का हम सब संकल्प लें, तो पंडितजी का सपना निश्चित सच होगा। ■

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' के सपने को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। 'जनधन योजना' के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। 'डीबीटी' यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसे पहुंचा कर भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया। 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई मिली।

पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाने को जल्द शुरू होगी केंद्रीय योजना

आईटीआई का होगा कायाकल्प

केंद्रीय कैबिनेट ने आईटीआई के उन्नयन और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू करने को दी मंजूरी

उद्योग जगत की कुशल मानव संसाधन जरूरतें पूरी करने के लिए पांच वर्ष में 20 लाख युवा होंगे कौशल विकास से लैस

स्थानीय कार्यबल आपूर्ति और उद्योग जगत की मांग के बीच तालमेल सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी योजना

युवा सहकार टीम

व्यावसायिक शिक्षा में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) के उन्नयन और कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की एक केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों और उद्योग जगत के सहयोग से मौजूदा आईटीआई को उद्योग जगत प्रबंधित कौशल संस्थान के रूप में स्थापित करना है। इसके माध्यम से पांच साल में 20 लाख युवाओं को ऐसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुशल बनाया जाएगा जिनसे उद्योग जगत की मानव संसाधन की जरूरतें पूरी होती हों। यह योजना स्थानीय कार्यबल आपूर्ति और उद्योग जगत की मांग के बीच तालमेल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इससे एमएसएमई (सूक्ष्म एवं लघु उद्योग) सहित उद्योग जगत को रोजगार के लिए तैयार श्रमिक उपलब्ध होंगे।

भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, आर्थिक विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देना जरूरी है। आईटीआई 1950 के दशक से ही देश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का मुख्य आधार रहे हैं जिनका संचालन राज्य सरकारों के अधीन होता है। आईटीआई के उन्नयन और कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा 2024-25 और 2025-26 के बजट में की गई थी। इसी घोषणा के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस योजना पर 60,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 30 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग जगत की 10,000 करोड़

रुपये होगी। केंद्रीय हिस्से में से आधी राशि (15,000 करोड़ रुपये) का सह वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा समान (7,500 करोड़ रुपये) रूप से किया जाएगा।

यह योजना उद्योग जगत के अनुरूप फिर से तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के साथ हब और स्पोक मॉडल के तहत 1,000 सरकारी आईटीआई के उन्नयन और 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसमें इन संस्थानों में कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी शामिल है। योजना के तहत प्रशिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण से जुड़ी सुविधाओं के लिए पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नत बनाया जाएगा। ये संस्थान भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त 50,000 प्रशिक्षकों को सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

हालांकि, आईटीआई को उन्नत बनाने के लिए पहले से कई योजनाएं चल रही हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता, विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर रखरखाव, क्षमता विस्तार और नए युग के व्यापारों की शुरूआत के लिए बढ़ती निवेश जरूरत के संदर्भ में आईटीआई की पूर्ण उन्नयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। इसे दूर करने के लिए नई योजना के तहत एक आवश्यकता आधारित निवेश प्रावधान रखा गया है। इसके तहत प्रत्येक संस्थान की विशिष्ट अवसंरचना, क्षमता और व्यापार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर राशि का आवंटन किया जाएगा। इस योजना में आईटीआई के प्रबंधन में उद्योग जगत को भी शामिल किया जाएगा ताकि परिणाम आधारित कार्यान्वयन रणनीति अपनाई जा सके। इससे आईटीआई का इकोसिस्टम बेहतर बनाया जा सकेगा।

इस योजना के माध्यम से इन्फ्रास्ट्रक्चर, पाठ्यक्रम प्रासंगिकता, रोजगार योग्यता और व्यावसायिक प्रशिक्षण की लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा। साथ ही, कुशल मानव संसाधान की आवश्यकता को पूरा करने में आईटीआई को सबसे आगे रखा जा सकेगा। यह उद्योग जगत की मांग के अनुरूप कुशल श्रमिकों को तैयार करेगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च विकास क्षेत्रों में कौशल की कमी को दूर किया जा सकेगा। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप है जिसमें वर्तमान और भविष्य की उद्योग जगत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल विकास को एक प्रमुख क्षमता प्रदाता के रूप में शामिल किया गया है।

पिछले एक दशक में आईटीआई के नेटवर्क में लगभग 47 प्रतिशत का विस्तार हुआ है। इसके बावजूद आईटीआई के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़ी आकांक्षा में कमी बनी हुई है। आईटीआई की पुनर्कल्पना के लिए पिछले दशक के प्रयासों को एक राष्ट्रीय योजना के माध्यम से विस्तार देने के लिए उद्योग की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन शामिल किया गया है, ताकि कुशल कार्यबल का एक समूह बनाया जा सके जो विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रमुख क्षमता प्रदाताओं में से एक हो। ■

इस योजना पर 60,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 30 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग जगत की 10,000 करोड़ रुपये होगी। केंद्रीय हिस्से में से आधी राशि (15,000 करोड़ रुपये) का सह वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा समान (7,500 करोड़ रुपये) रूप से किया जाएगा।

दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखा रहे भारतीय युवाः पीएम

15वें रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का किया वितरण

भारतीय युवा अपने समर्पण और नवाचार से आज दुनिया को दिखा रहे हैं कि हममें कितना सामर्थ्य हैः पीएम

युवा राष्ट्र निर्माण में प्रमुखता से योगदान देता है, तो देश तेज विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान बनाता है

युवा सहकार टीम

किसी भी राष्ट्र की प्रगति और सफलता की नींव उसके युवाओं में निहित है। युवा राष्ट्र निर्माण में भागीदार होते हैं, तो देश तेजी से विकास करता है और विश्व भर में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत के युवा अपनी कड़ी मेहनत और नवाचार के जरिये दुनिया को अपनी अपार क्षमता दिखा रहे हैं। सरकार भी यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते रहें। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं। इन अभियानों के माध्यम से सरकार देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक खुला मंच प्रदान कर रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप एक दशक में भारत के युवाओं ने देश को प्रौद्योगिकी, डेटा और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने (26 अप्रैल, 2025) रोजगार मेले के माध्यम से केंद्र के विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि

युवाओं के कर्तव्यों में देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करना, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान देना और श्रमिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाना शामिल है। जिस ईमानदारी के साथ वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, उसका भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इस दौरान यूपीआई, ओएनडीसी और जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलता का जिक्र किया जो दर्शाता है कि कैसे युवा डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलावों का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत अब डिजिटल लेनदेन में दुनिया में अग्रणी है और इस उपलब्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवाओं को जाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'बजट में घोषित मैन्युफैक्चरिंग मिशन का उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को वैश्विक स्तर पर मानकीकृत उत्पाद बनाने के अवसर प्रदान करना है। इस पहल से न केवल देश भर में लाखों एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को मदद मिलेगी, बल्कि देश भर में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक अभूतपूर्व समय है।' प्रधानमंत्री के अनुसार, हाल के दिनों में ऑटोमोबाइल और फुटवियर उद्योगों ने उत्पादन और निर्यात में नए रिकॉर्ड हासिल किए हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए हैं। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों ने पहली बार 1.70 लाख करोड़ रुपये के कारोबार को पार कर लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों नए रोजगार पैदा हुए हैं।

इसी तरह, 2014 से पहले अंतरदेशीय जल परिवहन के माध्यम से सालाना केवल 1.8 करोड़ टन माल की आवाजाही होती थी जो अब बढ़कर 14.5 करोड़ टन से अधिक हो गई है। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या भी 5 से बढ़कर 110 से अधिक हो गई है और इन जलमार्गों की परिचालन लंबाई लगभग 2,700 किलोमीटर से बढ़कर

लगभग 5,000 किलोमीटर हो गई है। ये उपलब्धियां पूरे देश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं।

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर फोकस

केंद्र सरकार स्वयं सहायता समूहों, बीमा सखियों, बैंक सखियों और कृषि सखियों जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिससे नए अवसर पैदा हुए हैं। देश में 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं जिनमें 10 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इन समूहों को मजबूत करने के लिए सरकार ने उनके बजट को पांच गुना बढ़ाया है और 20 लाख रुपये तक के कोलेटरल फ्री लोन का प्रावधान किया है। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी भी महिलाएं हैं। देश में 50,000 से अधिक स्टार्टअप में महिलाएं निदेशक हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के परिवर्तनकारी बदलाव भारत के विकास के संकल्प को मजबूत कर रहे हैं और रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर पैदा कर रहे हैं।

रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। ■

'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने और युवाओं को वैश्विक अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया मैन्युफैक्चरिंग मिशन। मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लाखों एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

स्विगी पर मिलेंगे सहकारी उत्पाद

युवा सहकार टीम

डिजिटल युग में उपभोक्ताओं की जरूरतें और खरीदारी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस अवसर का लाभ उठाने और नए ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने फूड डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट से समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। इसके तहत स्विगी के प्लेटफॉर्म से सहकारी उत्पादों की बिक्री देशभर में की जाएगी। इससे न सिर्फ सहकारी उत्पादों की पहुंच आमजन तक सुलभ होगी, बल्कि इनकी बिक्री बढ़ने से सहकारी समितियों का कारोबार बढ़ाने और उनका विस्तार करने में भी मदद मिलेगी।

देशभर के उपभोक्ताओं तक सहकारी और जैविक उत्पाद की पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने स्विगी इंस्टामार्ट से किया एमओयू।

केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी की उपस्थिति में स्विगी इंस्टामार्ट के सीईओ अमितेश झा और सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव डी.के. वर्मा ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्विगी के डिजिटल प्लेटफॉर्म और उसकी पहुंच का लाभ उठाकर भारत में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना है। यह साझेदारी स्विगी के प्लेटफॉर्म पर सहकारी डेयरी उत्पादों को शामिल करने को प्रोत्साहित करेगी और सहकारी संस्थाओं के लिए अधिक दृश्यता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समर्थन प्रदान करेगी। एमओयू के माध्यम से सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीक और प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर नए जमाने के ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। इससे 'भारत ऑर्गेनिक्स' और अन्य सहकारी एवं सहकारी डेयरी उत्पाद अब स्विगी के ई-कॉमर्स और क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध होंगे।

इस एमओयू के तहत स्विगी के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित सहकारी श्रेणी बनाई जाएगी, जिसमें ऑर्गेनिक्स, डेयरी, श्री अन्न (बाजरा एवं अन्य मोटे अनाज), हस्तशिल्प और सहकारी संगठनों द्वारा बनाए गए अन्य उत्पादों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे सहकारी उत्पादों को एक नई पहचान और व्यापक उपभोक्ता आधार मिलेगा। स्विगी सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर सहकारी ब्रांडों की मार्केटिंग, प्रचार, उपभोक्ता तकनीक और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेगा। यह पहल सहकारी संगठनों को उनकी डिजिटल उपस्थिति बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहने में मदद करेगी। इसके अलावा, स्विगी और सहकारिता मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान देशभर में सहकारी आंदोलन, संगठनों और उत्पादों के प्रचार के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाएंगे।

भारत में सहकारिता एक सशक्त सामाजिक-आर्थिक आंदोलन रहा है जो ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने अपने गठन के करीब चार साल में सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 60 से अधिक पहल की है। सहकारी क्षेत्र के जैविक उत्पादों सहित सहकारी उपज को बाजार तक पहुंचाने के प्रमोशन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ■

युवाओं में जागरूकता बढ़ाए एनवाईसीएसः नड्डा

युवा सहकार टीम

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए सहकारिता के प्रति लोगों, खासकर युवाओं में और जागरूकता बढ़ाने का सुझाव दिया है। सहकारिता से ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने से ही 'सहकार से समृद्धि' के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा किया जा सकेगा। एनवाईसीएस के अध्यक्ष राजेश पांडे ने जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की थी। इसी दौरान उन्होंने यह सुझाव दिया। इस मुलाकात में उन्हें एनवाईसीएस की निरंतर गतिविधि और प्रगति से अवगत कराया गया।

एनवाईसीएस अध्यक्ष ने उन्हें संगठन की पहल की जानकारी दी जो युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षित करने और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से रोजगारोन्मुखी और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए युवा सशक्तीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। राजेश पांडे ने उन्हें बताया कि एनवाईसीएस ने अपनी स्थापना के 26 वर्षों मे डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका के माध्यम को सुनिश्चित किया है। भेंट स्वरूप उन्हें एनवाईसीएस की मासिक पत्रिका 'युवा सहकार' भी दी गई और एनवाईसीएस द्वारा सहकारिता के उद्देश्य से युवाओं के उत्थान के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई।

एनवाईसीएस युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में काम करती है। युवाओं की इस कोऑपरेटिव सोसायटी की मुख्य गतिविधियों में माइक्रो फाइनेंसिंग, युवाओं को सुविधा उपलब्ध कराना, स्वयं सहायता समूह बनाना, उद्यमिता विकास और युवाओं एवं अन्य हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना शामिल है ताकि उनका आर्थिक सशक्तीकरण हो सके। अपनी स्थापना के बाद से ही एनवाईसीएस पूरे देश में उद्यमिता विकास और युवाओं को उद्यमी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्हें मार्केटिंग स्किल, सॉफ्ट स्किल, मैनेजमेंट स्किल, टीम प्रबंधन, नेतृत्व प्रबंधन और जीवन कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। एनवाईसीएस विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित करती है।

एनवाईसीएस की गतिविधियों की सराहना करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, 'मोदी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रिका के माध्यम से सहकारिता संबंधी जानकारी प्रदान करना और लोगों को सहकारिता के प्रति जागरूक करना एक सराहनीय कार्य है।' उन्होंने सहकार से समृद्धि पर नजर रखते हुए संगठन को कई सुझाव दिए और कहा कि केंद्र सरकार ने सहकारिता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अलग-अलग तरह कि समितियां बनाई हैं।

इस बैठक में आगे की योजना पर भी चर्चा की गई, जिसमें सहकारिता के क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। युवा सहकार इस दिशा में और अधिक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनवाईसीएस ने युवा सहकार के लिए इस बैठक के बाद कुछ विशेष पहल करने का निर्णय लिया है, जिसमें पाठकों के लिए और अधिक उपयोगी सामग्री प्रदान करने के निरंतर प्रयास किए जाएंगे और स्वास्थ्य एवं सहकारिता के मुद्दों पर और अधिक प्रकाश डाला जाएगा। ■

सोनवणे किशोरभाई की प्रेरक यात्रा में एनवाईसीएस का अमूल्य योगदान

आज, 'इन्फिनिटी हेयर सैलून' एक सफल व्यवसाय के रूप में फल-फूल रहा है। इसकी सफलता न केवल किशोरभाई के अथक परिश्रम और समर्पण का परिणाम है, बल्कि एनवाईसीएस की दूरदर्शी सोच और युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है।

युवा सहकार टीम

सोनवणे किशोरभाई विक्रमभाई एक युवा और दृढ़ निश्चयी उद्यमी हैं, जिनके मन में अपने भविष्य को बेहतर बनाने और अपने समुदाय को सशक्त बनाने का सपना था। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें एक सही मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। इसी संकल्प और विश्वास के साथ किशोरभाई ने नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) की गुजरात स्थित व्यारा शाखा से संपर्क किया।

उन्होंने एनवाईसीए से 1,00,000 रुपये का ऋण प्राप्त किया और अपने सपनों का व्यवसाय 'इन्फिनिटी हेयर सैलून' की स्थापना की। यह सैलून न केवल स्थानीय ग्राहकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ग्रूमिंग सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है।

किशोरभाई का कहना है, 'मैं एनवाईसीएस का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरे सपने को उड़ान दी। इस सहायता ने मुझे आत्मनिर्भर और एक युवा उद्यमी के रूप में आत्मविश्वासी बनने में मदद की।'

आज, 'इन्फिनिटी हेयर सैलून' एक सफल व्यवसाय के रूप में फल-फूल रहा है। इसकी सफलता न केवल किशोरभाई के अथक परिश्रम और समर्पण का परिणाम है, बल्कि एनवाईसीएस की दूरदर्शी सोच और युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है।

एनवाईसीएस का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि देश के युवाओं को सही समय पर आवश्यक सहायता प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए। किशोरभाई की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब युवाओं को

अवसर और संसाधन दिए जाते हैं, तो वे न केवल अपना जीवन संवार सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

आज किशोरभाई अपने इलाके के युवाओं के बीच एक प्रेरणास्रोत बन चुके हैं। उनकी सफलता की कहानी से यह संदेश स्पष्ट होता है कि सही सहयोग और आत्मविश्वास के साथ कोई भी सपना साकार किया जा सकता है।

एनवाईसीएस के प्रयासों ने न केवल एक युवा का भविष्य उज्ज्वल किया, बल्कि एक पूरे समुदाय को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। किशोरभाई सोनवणे की सफलता यह साबित करती है कि जब सपनों को सहयोग मिलता है, तो वे समाज के परिवर्तन का आधार बन सकते हैं।

एक कदम सपनों की ओर

एनवाईसीएस का उद्देश्य सिर्फ ऋण प्रदान करना नहीं है, बल्कि युवाओं के सपनों को उड़ान देना भी है। रोनितभाई धोड़िया की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सपनों को साकार करने के लिए केवल हौसला ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही सहयोग भी आवश्यक होता है। बचपन से ही रोनितभाई का सपना था कि वे अपने क्षेत्र में एक आधुनिक डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना करें, ताकि ग्रामीण इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ हो सकें।

मेडिकल परीक्षण के क्षेत्र में रोनितभाई के पास गहरी जानकारी और व्यावसायिक अनुभव था, लेकिन अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। इस समय रोनितभाई ने सहायता के लिए गुजरात में नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) की व्यारा शाखा की ओर कदम बढ़ाया।

रोनितभाई की विस्तार क्षमता को पहचानते हुए एनवाईसीएस ने अपने सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत 3,00,000 रुपये का लोन प्रदान किया। यह सहयोग उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस राशि से रोनितभाई ने आधुनिक लैब उपकरण खरीदे, स्वच्छ और पूर्णतः सुसज्जित प्रयोगशाला की स्थापना की साथ ही प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की ताकि सटीक और समय पर जांच सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।

कुछ ही महीनों में तापी क्लीनिकल लेबोरेटरी ने स्थानीय समुदाय में अपनी विश्वसनीयता और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एक विशेष पहचान बना ली। आज यह लैब हर महीने सौ से अधिक मरीजों को सेवा प्रदान कर रही है। रोनितभाई की इस पहल ने न केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाई है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं।

रोनितभाई कहते हैं, 'जब मुझे सबसे अधिक जरूरत थी, तब एनवाईसीएस ने मेरे सपनों पर विश्वास किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं अपने समुदाय की सेवा कर रहा हूँ और अपने शहर में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर रहा हूँ। यह यात्रा एनवाईसीएस के समय पर मिले सहयोग के बिना संभव नहीं थी।'

रोनितभाई धोड़िया की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब संस्थाएं विश्वास के साथ समर्थन करती हैं, तो व्यक्ति न केवल अपनी दिशा बदलता है, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।

आज तापी क्लीनिकल लेबोरेटरी एक मिसाल बन चुकी है कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद, सही मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग से बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं। व्यारा शाखा ने एक और बार यह सिद्ध कर दिया कि वे भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने में एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े हैं।

एनवाईसीएस न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि उद्यमिता को बढ़ावा देकर स्थानीय विकास को भी गति देता है। रोनितभाई जैसे उदाहरण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और समर्थन सच्चा मिले, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। ■

एनवाईसीएस न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि उद्यमिता को बढ़ावा देकर स्थानीय विकास को भी गति देता है।

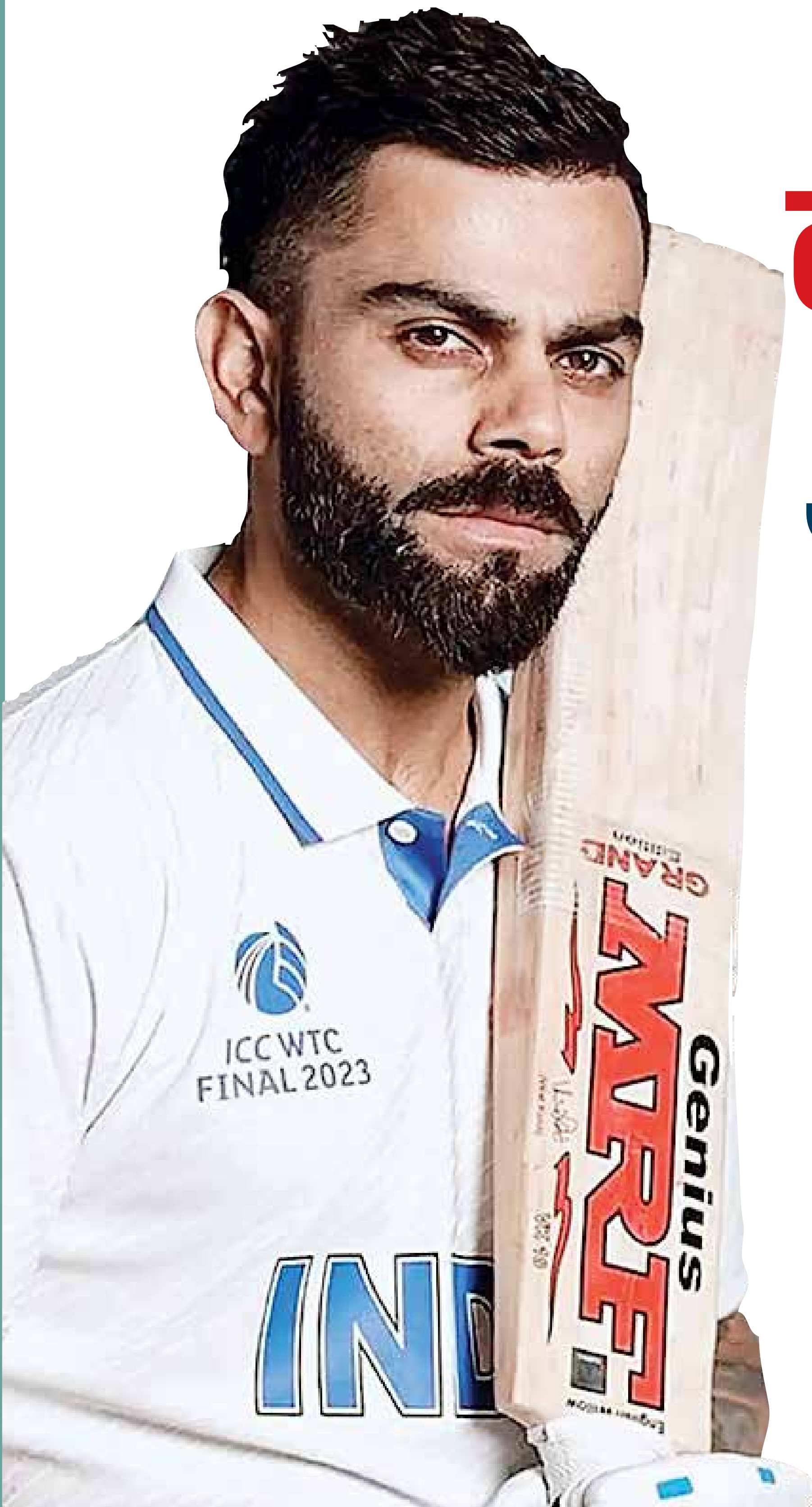

टेस्ट को कोहली की अलविदा

अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की विराट कोहली ने की घोषणा, टी-20 से पहले ही ले चुके हैं संन्यास, अब सिर्फ वनडे ही खेलेंगे

सत्येंद्र पाल सिंह

भारत और दुनिया के तीनों फॉर्मेट के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने कुल 123 टेस्ट खेले और 46.85 की औसत से 30 शतकों और 31 अर्द्धशतकों की मदद से 9,230 रन बनाए हैं। कोहली 10 हजार रन बनाने से केवल 770 रन दूर थे। इस बड़े मुकाम तक पहुंचने से पहले ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला चौंकाने वाला है। टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने के मामले में वह 19वें स्थान पर हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट खेल 51 शतकों और 68 अर्द्धशतकों सहित 15,921 रन बना कर दुनिया में शीर्ष पर हैं।

विराट उन खुशकिस्मत क्रिकेटरों में से एक हैं जिन्हें भारत को 2011 में मुंबई में

आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप और 2024 में आईसीसी टी-20 क्रिकेट विश्व कप जिताने का गौरव हासिल है। हालांकि, भारत को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताने की उनकी कसक तब अधूरी रह गई जब टीम इंडिया लगातार दो बार फाइनल में पहुंच कर भी इससे जीतने से चूक गई। कोहली ने 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की और इसमें 40 जीते, 17 हारे और 11 ड्रॉ रहे। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया घर से बाहर 16 और घर में 24 टेस्ट जीतने में कामयाब रही। वह भारत के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान होने के साथ दुनिया के चौथे सबसे कामयाब कप्तान हैं। बीते बरस वेस्टइंडीज में आईसीसी टी-20 क्रिकेट विश्व कप जिताने के बाद रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा के साथ वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही अलविदा ले चुके हैं।

> **अब जब मैं टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं, तो मेरे लिए यह कतई आसान फैसला नहीं है, लेकिन मुझे यही सही लगता है। मैंने टेस्ट क्रिकेट को अपना सब कुछ दिया है और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है। मैं दिल से आभार के साथ टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहाझ्र खेल के लिए, उन लोगों के लिए जिनके साथ मैंने मैदान साझा किया और हर एक व्यक्ति के लिए जिसने मुझे इस दौरान महसूस कराया। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा।**
>
> **विराट कोहली**

शुभमन गिल या जांबाज ऋषभ पंत में से भले ही किसी को भी दी जाए, लेकिन अब विराट के भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने की घोषणा से सेलेक्टर्स को सही एकादश चुनने के लिए बहुत माथापच्ची करनी होगी। भारत के पूर्व टेस्ट ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू की मानें, तो इन दोनों के जाने के बाद भारत के लिए इंग्लैंड दौरे की टीम और सही एकादश चुनना बेहद मुश्किल चुनौती होगा।

विराट कोहली 9230 रन के साथ भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चौथे नंबर पर हैं। 30 टेस्ट शतकों के साथ भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने में भी चौथे नंबर पर हैं। उन्हें भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सात दोहरे शतक जमाने का गौरव हासिल है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लगातार दो कैलेंडर बरस में 75 या इससे ज्यादा की औसत से एक हजार से ज्यादा रन बनाने वाले वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। विराट का पहला बड़ा इम्तिहान 2014-15 का ऑस्ट्रेलिया दौरा था जहां उन्होंने एडिलेड टेस्ट में दो शतक और फिर मेलबर्न और सिडनी टेस्ट में भी शतक सहित कुल चार शतकों के साथ 86.50 की औसत से कुल 692 रन बनाए थे।

विराट ने सोशल मीडिया पर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने की घोषणा करते हुए लिखा, 'टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बैगी ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि टेस्ट क्रिकेट मुझे किस सफर पर ले जाएगा। टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली। मुझे टेस्ट क्रिकेट ने बतौर क्रिकेटर संवारा और ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर संजोए रखूंगा। सफेद जर्सी में खेलना बहुत ही निजी अनुभव होता है। शांत, परिश्रम, लंबे दिन, छोटे-छोटे पल, जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन ये पल हमेशा आपके साथ रहते हैं। अब जब मैं टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं, तो मेरे लिए यह कतई आसान फैसला नहीं है, लेकिन मुझे यही सही लगता है। मैंने टेस्ट क्रिकेट को अपना सब कुछ दिया है और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है। मैं दिल से आभार के साथ टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहा- खेल के लिए, उन लोगों के लिए जिनके साथ मैंने मैदान साझा किया और हर एक व्यक्ति के लिए जिसने मुझे इस दौरान महसूस कराया। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा।'

रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के एक महीने के भीतर विराट कोहली की इस घोषणा से टीम इंडिया को झटका लगा है क्योंकि 20 जून से इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैच खेले जाने हैं जिसमें ये दोनों दिग्गज नहीं होंगे। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने और जसप्रीत बुमराह के इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने की अनिच्छा से कप्तानी

कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं। तीनों फॉर्मेट को मिला कर में वह कुल 82 शतक जड़ चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 100 शतक सचिन तेंदुलकर के नाम हैं। टी-20 व टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के बावजूद विराट के पास सचिन के 100 शतकों के रिकॉर्ड तक पहुंचने या उसे तोड़ने का मौका है क्योंकि वह अभी भी वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि विराट ने अपने करियर में 302 वनडे मैच खेल 51 शतकों और 74 अर्द्धशतकों सहित 14,181 रन बनाए हैं।

विराट ने पहले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को बता दिया था कि वह टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते हैं। तब बीसीसीआई ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी और अपने जमाने के शीर्ष क्रिकेटर को उन्हें कम से कम इंग्लैड सीरीज तक के लिए रुक जाने को मनाने का जिम्मा सौंपा, लेकिन विराट अपने फैसले पर काबिज रहे। ■

लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं।

पैक्स का कारोबारी दायरा बढ़ने से बदल रहा ग्रामीणों का जीवन

युवा सहकार टीम

प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) को आर्थिक रूप से व्यावहारिक और ग्रामीणों की सुविधा का केंद्र बनाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जो पहल की थी उसके नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप खोलने, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप सहित 25 से ज्यादा कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की पैक्स को मंजूरी दी गई है। पैक्स की कारोबारी गतिविधियां बढ़ीं तो ग्रामीण लोगों के जीवन में बदलाव दिखने लगा। अब उन्हें छोटे से छोटे काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद का एक छोटा सा गांव है पहाड़पुर, जो कभी बुनियादी सेवाओं की कमी से जूझता था। मगर आज यही गांव राज्य के डिजिटल और सहकारी मॉडल की मिसाल बन गया है। इस बदलाव की कहानी एमपैक्स (मल्टीपर्पस पैक्स) और सीएससी के संयोजन से शुरू होती है। यहां के पैक्स में जब से कॉमन सर्विस सेंटर खुला है तब से गांव के लोगों को अपनी सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। उन्हें गांव में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद का एक छोटा सा गांव है पहाड़पुर, जो कभी बुनियादी सेवाओं की कमी से जूझता था। मगर आज यही गांव राज्य के डिजिटल और सहकारी मॉडल की मिसाल बन गया है।

गांव के लोग पहले अपना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनवाने के लिए तहसील के चक्कर लगाते थे। अब उन्हें ये सारी सुविधाएं पैक्स के सीएससी पर ही मिलने लगी हैं। इसी तरह, बैंकिंग सेवाओं, केवाईसी अपडेट और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था। सीएससी की वजह से अब ये सभी सेवाएं गांव में ही सिंगल विंडो पर उपलब्ध हैं। सीएससी को करीब 300 सेवाएं देने के लिए अधिकृत किया गया है।

40,330 से अधिक पैक्स ने ग्रामीण जनता को सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरु कर दिया है। अब तक पैक्स द्वारा 46.65 करोड़ रुपये का लेनदेन किया जा चुका है।

पहाड़पुर गांव के किसान विवेक सिंह कहते हैं, 'पहले हमें यूरिया के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। अब मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि खाद आ गई है। हम सीधा पैक्स पर जाकर ले आते हैं और वह भी निर्धारित मूल्य पर। पैक्स के माध्यम से अब किसानों को नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और अन्य उर्वरक जैसी कृषि सामग्री समय पर और सही दाम पर मिल रही है। वहीं सीएससी के जरिये डिजिटल प्रमाण पत्र, बैंकिंग सुविधाएं और सरकारी योजना का लाभ सरलता से मिल रहा है।

गांव की महिलाओं और युवाओं के लिए यह केंद्र रोजगार और सम्मान का माध्यम बन गया है। तकनीकी और सहकारी बदलाव ने पहाड़पुर को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को खेत खलिहानों तक पहुंचाया है। किसानों को अपनी खेती के लिए जरूरी खाद, बीज, कीटनाशक और बैंकों के लोन आदि भी पैक्स और सीएससी के माध्यम से मिल जाता है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अब मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ■

National Yuva Co-operative Society Limited

NYCS

Empowering Financial Independence

Our Services

Loans: Small, medium, and large loans at highly competitive interest rates, catering to the diverse financial needs of our members.

Deposits: Attractive interest rates, with special benefits for senior citizens and women.

Simplified Process: Our streamlined application process and flexible terms ensure that financial assistance is always within reach.

Our Reach

- Presence in All States & Union Territories
- 37 Branches Nationwide
- 600+ Districts Served by Our Representatives
- Central Administration Office (CAO) in Pune, Led by Senior Banking & Finance Professionals

Why Choose NYCS Ltd.?

- **Trusted Expertise** – Over 20 years in financial services.
- **Nationwide Presence** – A rapidly growing network.
- **Member-Focused** – Tailored financial solutions.
- **Youth Empowerment** – Supporting young entrepreneurs.

Contact Us

209, 2nd Floor, A2B, Vardhman Janak Market, Janakpuri, New Delhi-58
+91 9205595944
011-45096652/40153681
nycs.ltd@gmail.com
www.nycsltd.com

Together, let's build a brighter financial future!

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

SERVING **FARMERS** **TO GROW** BOUNTIFUL

KRIBHCO world's premier fertilizer producing cooperative has been consistently making sustained efforts towards promoting modern agriculture and cooperatives in the country. It helps farmers maximize their returns through specialised agricultural inputs and other diversified businesses.

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD

Registered Office: A-60, Kailash Colony, New Delhi-110048 | **Phone: 011-29243412**
Corporate Office: KRIBCHO BHAWAN, A 8-10, Sector-1, Noida-201301, Distt: Gautam Budh Nagar (UP) | **Phones:** 0120-2534631/32/36
Website: www.kribhco.net | **KRIBCHO Kisan Helpline:** 0120-2535628 | **E-mail:** krishipramarsh@kribhco.net

OUR PRODUCTS

Neem Coated Urea | DAP | MOP | NPK | NPS | MAP | Liquid Bio Fertilizers | Certified Seeds | Hybrid Seeds City Compost | Zinc Sulphate | Natural Potash | Sivarika | Rhizosuper